

anything more is required than what the Prime Minister has stated here. I do not think anything more is required than what the Prime Minister has stated here. I do not think that there, is any kind of discussion. . . (Interruptions). But since we are meeting at 4 o'clock in the Business Advisory Committee, certainly we would like to consult the Chairman also in this matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What I feel is. . . (Interruptions). I have a suggestion, please. As the Home Minister and Leader of the House has suggested, the procedure will be decided in the BAC. Whether the Business Advisory Committee take it up or not, it cannot be decided in this House. That matter is closed now. Pandeyji.

## RE BOMB EXPLOSIONS IN

डा० शम्भाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) :  
उपसभापति महोदया, पिछले तीन दिनों के भीतर दिल्ली में तीन बम विस्फोटों की घटनाएं हुई हैं। इसकी शुरुआत 29 जनवरी को हुई जब कि तिमारपुर क्षेत्र में एक डी० टी० सी० के बस में अक्षिशाली बम फटने से 4 लोग मारे गए और 27 लोग घायल हुए। 23 तारीख को पहाड़गंज के लूमा होटल में 14 व्यक्ति घायल हुए जिनमें कुछ विदेशी भी थे। तीसरा विस्फोट 25 अप्रैल की रात को लाल किले के पास एक डी० टी० सी० बस में हुआ जिसमें 8 व्यक्ति घायल हुए और कल उर्दू बाजार में एक बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ मारा गया और पांच व्यक्ति घायल हुए। आए दिन बम विस्फोट की घटनाएं दिल्ली में आम हो गई हैं और सामान्य नागरिकों को जीवन खतरा हो गया है। इन विस्फोटों में खाइकुओं का हाथ है और यह कहा जाता है कि वे टीगर बमों का प्रयोग करते हैं जब कि अन्य आतंकवादी फ्युज बमों का प्रयोग करते हैं। कल और परसों जाआ मस्जिद और लाल किले के पास बस में जो दुर्घटनाएं हुई हैं

उसमें रशियन बम का लेबल मिला है उसमें खुदा हुआ मिला है। इस तरह से दिल्ली के नागरिकों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। खाइकु संगठन, आतंकवादी संगठन तथा विदेशी ताकतें इस देश की राजधानी में आतंक मचा कर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में पुलिस को और सतर्कता विभाग को और भी चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है और अगर संभव हो तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के ज़िम्मे दिल्ली को सौंप देना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि गृहमंत्री जी इस संबंध में स्टेटमेंट सदन में दें ताकि बम विस्फोट की घटनाएं जो आए दिन और प्रति दिन लगातार हो रही हैं वे बंद हो जाएं और दिल्ली के नागरिकों का जीवन खतरा न हो और आतंकवादियों के छाया तले दिल्ली में जो देश की राजधानी में है वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न हों। इस लिए मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ी चिन्ता की बात है। शुरू से ही दिल्ली में बराबर आतंकवादी एक्टिविटीज चलती आ रही हैं। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं वह हिन्दू, मुसलमान सब का सदभाव मिटाकर निरीह बच्चों और विदेशी नागरिकों तक को काल के गाल में डाल रहे हैं। आज राजधानी में बम विस्फोट से जन-जीवन खतरा है। हो सकता है कि संसद में भी एक दिन बम फट जाए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे भी हो गृहमंत्री जी इस पर सारी सूचनाएं लेकर कि वें इस संबंध में क्या उपाय कर रहे हैं, यह सदन को बताएं और एक स्टेटमेंट देकर इस संदर्भ में सारी जिज्ञासियों को शांत करें। धन्यवाद।

THE VICE-PRESIDENT, (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR J.Mr. Home Minister, would you like to respond?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): I have taken note of what he has said.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, डा० रत्नाकर पाण्डे जी ने दिल्ली में होने वाली जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वे बहुत ही चिंतनीय हैं। देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएँ हो इससे बढ़ाकर चिंताजनक कोई बात हो नहीं सकती।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोडकर) यादव जी सुनिए, होम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। सुनिए।  
Please sit down. The Home Minister is saying something.

श्री शंकर ब्यास सिंह (बिहार) : एक सकेड। आपने डा० रत्नाकर पाण्डेय जी को समय दिया। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोडकर) : अच्छी बात नहीं, बहुत दुःखदायक बात कही।

श्री शंकर ब्यास सिंह : एक मिनट सुनें। जो बातें उन्होंने कही वह बहुत चिंतनीय हैं। दिल्ली में जिस तरह की आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं वह चिंता का विषय है। लेकिन आज अखबारों में मुख पृष्ठ पर आया है कि इस चिंता से दिल्ली की जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार ने दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर श्री मार्कण्डेय सिंह को हटाया है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि जिन दूसरे राज्यों में इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं, वहाँ भी इसी कड़ाई के साथ सरकार कदम उठाएगी ?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): This does not arise out of this.

श्री शंकर ब्यास सिंह : और क्या सरकार आश्वासन देगी कि जो नए लेफ्टीनेंट गवर्नर आयेंगे उनके रहते इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let him make the statement. Pandeyji, please sit down. Please take your seat. Let the Home Minister respond.

SHRI S. B. CHAVAN; Sir, I fully agree with my honourable friend, Shri Ratnakar Pandey. It is a matter of great concern to the Government also that such a thing should ever happen in this city. The matters are under investigation and unless we get some kind of a clue, it will not be proper on my part to make and kind of statement before the investigation are completed.

SHRI DOVIO LEDGER (Assam): Sit with deep anguish and distress, I beg to state that the administration of Assam has been handed over to the Army. Sir if I remember correctly, the honourable Home Minister, who is present here now had categorically stated on the floor of this House that the Army had been sent to Assam to aid and assist the civil authorities. It is surprising to note that the Chief Minister of Assam has today publicly stated that the "Operation Rhino II was launched in Nalbari and Darrang district without his knowledge and without the knowledge of the State administration or the concerned district administration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please make your point briefly.

SHRI DAVID LEDGER: I am coming to my point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is because this is not a Special Meeting, but this is a Zero Hour matter.

SHRI DAVID LEDGER; Sir, the Chief Minister is pleading ignorance about the goings-on in this State with regard to matters of Army operation and because of this, people have lost their lives, innocent people have lost their lives and I have no moral right to remain in power. May I submit, Sir, that there is total abdication of responsibility on the part of the Chief Minister and also the State.

Government? Two innocent people have lost their lives. The Army resorted to unprovoked firing on a marriage party in which a veterinary doctor, Dr. Jayanta Saikia, and a veterinary student, who had come all the way from Sikkim to study veterinary science in the college there, had lost their lives. I demand that a proper judicial inquiry be instituted against the killing of the innocent people and I also demand that the Chief Minister of Assam besacked forthwith. Thank you, Sir.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, may I make a suggestion? Can we dispense with the lunch hour today so that the business can be transacted?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We have not come to the lunch hour as yet.

SHRI S. JAIPAL REDDY: As an Opposition Member, I am making this suggestion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is all right. But we are beginning the Session only today and I do not know whether we can do it now.

श्री भूपेन्द्र सिंह धान (नाम-निर्देशन): वाइस-चेयरमैन सर, मैं उस मूढ़ पर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में हम सब को बहुत चिंता होनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में गेहूँ की फसल आ गई है। सरकार ने सपोर्ट प्राइज फिक्स की है। सपोर्ट प्राइज का मतलब होता है कि अगर उससे भाव कम होंगे तो सरकार किसानों की मदद पर आयेगी, एक और दूसरा जोनल रिसट्रिक्शन व्हीट की मूवमेंट पर कहीं नहीं है, वह टूट गया है। और तीसरा इस वक्त इस देश में खुलेपन की पालिसी चल रही है। कोई भी चीज़ कहीं ले जा सकते हैं। चौथा यह कि इस देश में

विधान का, कानून का राज है। इन चारों बातों को देखते हुए मैं आप से यह कहना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब में गेहूँ मंडियों में आई है। वह कहीं भी जा सकती है। सपोर्ट प्राइस से नीचे गिरे तो सरकार खरीदे लेकिन जब कोई व्यापारी उस गेहूँ को सपोर्ट प्राइज के ऊपर खरीदता है तो सरकार ऐसे हथकंडे अख्तियार करती है कि उससे ऊपर उसको खरीदने नहीं देती है। जैसे अगर कोई आठवीं ज्यादा कीमत पर किसी व्यापारी को बेंचे तो उसका लाइसेंस कैंसिल करना है यह बहुत जरूरी बात है आप इसको समझते हैं कि यह जरूरी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान इस वक्त इतने एंजीटेड हैं। वह देख रहे हैं कि हम तो जैसे गुलाम बने हुए हैं। यह बात बहुत गम्भीरता से ली जानी चाहिए। जहां तक मवमेंट का सवाल है, जब कोई ट्रक के ऊपर गेहूँ लोड करता है तो हलांकि मवमेंट कंट्रोल आर्डर कोई नहीं है, रिसट्रिक्शन कोई नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रक वालों को पकड़ कर के चलाया जाता है कि तुम्हारी लाइसेंस नहीं है, ब्रेक बस्ती नहीं है, कागज़ दिखाओ, उसको हर तरह से हरास किया जाता है। कानून में जो सुविधा दी गई है कि वह अपना गेहूँ कहीं भी ले जा सकता है लेकिन गैर कानूनी ढंग से उसको पुलिस वाले और सरकार रोकती है, तंग करती है, आगे नहीं ले जाने देती है। एफ० सी० आई० वाले या दूसरे प्रोक्योरमेंट एजेंसियां जो गेहूँ प्रोक्योर करती हैं, जब वहां प्रोक्योर करने के लिए जाते हैं (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You are in zero hour. This is not a Special Mention.

श्री भूपेन्द्र सिंह धान : मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गेहूँ मंडियों में आई है। किसानों की करोड़ों रुपये की लूट हो रही है। सरकार जान बूझ कर के यह लूट कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या हमें यह कहने का

[श्री भूपेन्द्र सिंह मान:]

हक नहीं है ? इस वक्त पंजाब और हरियाणा में जो सरप्लस गेहूं है वहां का किसान यह सोचे कि जैसे हम गुलाम हैं, हमारा कोई हक नहीं है कि हम गेहूं बाहर ले जा सकें, क्या हम कोई दूसरे देश में रहते हैं ? इसलिए यह सोचने वाली और बड़ी गम्भीर बात है। पहले ही सेंटीमेंट ऐसे बढ़े हुए हैं पंजाब में। आपने पंजाब में गेहूं का भाव 280 रुपये प्रति क्विंटल दिया है और बाहर 450-500 रुपये का भाव चल रहा है तो हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जाता है। गैर कानूनी ढंग से पाबंदी लगाई गई है कि ढाई सौ क्विंटल से ज्यादा गेहूं नहीं खरीद सकते, ट्रक नहीं ले जा सकते सरपाया देने पर पाबंदी लगाई गई है। यह सारी गैर कानूनी पाबंदी जो लगाई गई है यह सिर्फ किसानों को बूटने के लिए लगाई गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस लूट को बंद करना चाहिए। सदन के सभी सदस्यों को चाहिए कि वह सरकार से यह कहें कि यह गैर कानूनी, गैर-वैधानिक हथ कड़ों की सरकार को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कोई चीज नहीं है तो फिर गेहूं को बाहर जाने से क्यों रोक जा रहा है ? यह गैर कानूनी है, गैर वैधानिक है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: इससे लोगों के जो वहां सेंटीमेंट्स हैं, उनसे लगता है कि जैसे किसी और देश की गेहूं किसी और देश में जाने वाली है। क्या हम कोई इंटरनेशनल बार्डर कास कर रहे हैं ? अगर गेहूं पंजाब से दिल्ली लावेंगे या महाराष्ट्र ले कर जाएंगे तो क्या दूसरे देश में ले जाने वाले हैं ? क्यों हमें ऐसा लगता है ? हमें ऐसा क्यों नहीं करने दिया जाता है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Mam, please conclude. You have made the point.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: इसलिये मैं चाहूंगा, यह इतना गम्भीर मामला है, इसको आप लाइटली न लें, इसकी गम्भीरता से लिया जाए। इससे जो मेसेज जा रहा है लोगों को वह बहुत गलत मेसेज जा रहा है। हरियाणा और पंजाब की ऐसी जो स्थिति पैदा हुई है, हमेशा उनकी इकोनॉमिक हालत खराब रही है क्योंकि किसानों को कुछ करने नहीं दिया जाता है। यह टेंडर दिया गया कि सरकार यह चाहती है कि गेहूं बाहर से मंगवाया जाए और यहां के किसानों ने सरकार को टेंडर दिया कि हम चार सौ रुपये प्रतिक्विंटल जितना आप चाहो उतना गेहूं आपको देने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई हिसाब की बात हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Mann, let us not dilate on it.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: क्यों हम ऐसा मेसेज देते हैं जिससे यह पता चले कि उनको लूटा जा रहा है, यह लूट बंद होनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit down. Government has taken note of it.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा): उपसभ्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव: यह बहुत ही गम्भीर मसला है। किसानों की खुली लूट हो रही है। किसानों के साथ ज्यादाती हो रही है और मैं समझता हूँ कि यह पूरे देश में के साथ ज्यादाती हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस बात को देखे कि किसानों की लूट बंद होनी चाहिए। मार्केट में जो गेहूं का भाव है, उसी दाम पर सरकार को खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए।

1-00 PM

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: (व्यवधान) और सिबिल सप्लाय के महकमे का

दुरुपयोग किया जा रहा है... (अवधान)  
किसानों के अनाज की सूट हो रही है।  
में सपोर्ट करना चाहता हूँ जो मान साहब  
ने कहा है। सरकार को चाहिये कि इस  
स्थिति के बारे में, गेहूँ की चीज के  
के बारे में इस हाउस के अंदर एक  
बायन दे और जो किसानों को रगड़ा  
मारा जा रहा है... (अवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You  
associate with the feelings of Mr. Mann.

श्री महेश सिंह साठर सरकार उसके  
लिए जिम्मेवार है। हरियाणा और  
पंजाब सारे देश को गेहूँ सप्लाई  
करता है। वाईस चेयरमैन सर यह  
इतना इम्पॉटेंट इश्यू है कि इसके  
ऊपर आग लग सकती है।  
हरियाणा और पंजाब के किसान गेहूँ  
पैदा करना बंद कर देंगे अगर उनके  
दाम उनको नहीं मिले। हम अमेरिका  
से साढ़े चार सौ... (अवधान) पर  
खरीद सकते हैं लेकिन अपने किसानों  
को ठीक मुआवजा नहीं दे सकते, उसका  
उसका पैसा नहीं दे सकते। यह जो  
मामला उठाया है मान साहब ने यह  
इतना गम्भीर मामला है कि सारे हाउस  
को इसके साथ एसोसिएट करना चाहिए  
और सरकार को आकर बयान देना  
चाहिए।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, I  
want to raise a small matter here, (Interruptions)

श्री शंकर बयाल सिंह उपसभाध्यक्ष  
महोदय, जो कुछ मान साहब और दूसरे  
साथियों ने उठाया है हम लोग भी इसके  
साथ एसोसिएट करते हैं। केवल यह  
हरियाणा और पंजाब के ही किसानों का  
मामला नहीं है बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश,  
बिहार और दूसरी सारी जगहों का है  
जहाँ कहीं भी रबी की फसल हो रही  
है, जहाँ धान की फसल बरबाद हुई है।  
लोगों की सारी माली हालत कायम होती

है गेहूँ और रबी की फसलों पर...  
(अवधान) हम लोग इसलिए एसोसिएट  
कर रहे हैं... (अवधान) देखिए, आपने  
खुद कहा कि सारा हाउस करे।  
कांग्रेस के लोग चुप हैं कोई उधर से अभी  
... (अवधान)

श्री राम नरेश दादव: किसानों का  
जो यह सवाल है... (अवधान) हमारे  
ही लोगों ने उठाया... (अवधान)

श्री शंकर बयाल सिंह: यादव जी,  
सरकार चुप है। माफ़ी कीजिएगा।  
कांग्रेस शब्द हटा लिया है। सरकार  
चुप है। हमको इसलिए बोलना जरूरी  
था: मान्यवर कि लोगों को यह जानकारी  
होनी चाहिए कि सभी दूसरी मेजर पार्टीज  
के लोग इसमें सहमती रखते हैं इसलिए  
हम लोग भी इसका साथ देते हैं।

एक माननीय सदस्य: गेहूँ का आयात  
बंद कर दिया है।

SHRI JOHN P. FERNANDES: Sir...

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI  
BHASKAR ANNAJI MASODKAR):  
You are also associating?

SHRI JOHN F. FERNANDES: Want to raise  
is a small matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
BHASKAR ANNANI MASODKAR): No, no. It is  
not permitted, Mr. Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES: It is  
a small matter, Sir. (Interruptions)

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): Sir,  
you should ask the Government to make a  
statement. Why is this restriction? The State  
Government has no right to put the restriction  
(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
BHASKAR ANNAJI MASODKAR):  
Mr. Jacob, the demand is that on this  
issue raised by Mr. Mann, the Government should  
make a statement. All the Parties are saying it,  
including your

[Shri Bhaskar Annaji Masodkar]

own Party. If you want to respond...  
(Interruptions)

SHRI P. UPENDRA (Andhra Par-desh):  
Are we dispensing with the Special  
Mentions?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
BHASKAR ANNAJI MASODKAR): They  
are already allowed...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, about  
the realignment of Konkan Rail-day,  
yesterday there was a peaceful demonstration.  
People were demanding the realignment of  
Konkan Railway from the coastal land to the  
hinterland. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us  
proceed with the Special Mentions.  
(Interruptions) Mr. Mathur, I am ruling in  
your favour. I am ruling that we proceed with  
the Special Mentions. Shri Upendra.  
(Interruptions) Mr. Fernandes, please sit  
down. I have indent!-fied Mr. Upendra.

#### SPECIAL MENTIONS

##### Agitation by tobacco growers in Andhra Pradesh

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh) :  
Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to refer  
the problem's faced by the tobacco growers of  
Andhra Pradesh. There has been some serious  
agitation for the last two weeks or more in  
Andhra Pradesh. Thousands of farmers have  
surrounded the Tobacco Boards office at  
Guntur. And there is serious unrest in the  
State.

Sir, at the beginning of the marketing  
season this year, in the first week of March,  
the average rate for F-1 and F-2 grades of  
tobacco was around Rs. 33 per cent per kg.  
Sir, suddenly it fell to Rs. 26, and there is no  
reasons for that because whereas last year the  
export price was Rs. 39 per kg., the traders  
this year are getting Rs. 60 per kg. because of  
fluctuation in the exchange rate and other  
factors. In

spite of that, they are not prepared to  
share the profits with the farmers. The  
traders attribute this slump to the ex  
cess production this year whereas the  
Tobacco Board says that the export or  
ders following the protocol signed with  
the Russian, Federation have not been  
implemented. As a result, the purchases  
have come to a standstill. The Russian  
Government so far contracted only for  
15 million kgs. of tobacco .....

SHRI VITHALBHAI M. PATEL  
(Gujarat): It is 25 million.

SHRI P. UPENDRA: Twentyfive mil  
lion was agreed to but only 15 million  
they have contracted so far, and the far  
mers have demanded that the remaining  
ten million Kgs. of leaf tobacco and  
three million kgs. of cigarettes also should  
be completed. All this trouble started  
because the traders have spread a word  
that the demand for tobacco this year  
would be 170 million kgs. both internal  
and for export, and this was supported  
by Mr. Chidambaram, Minister of Com  
merce, when he visited Guntur in De  
cember last year, stating that the farmers  
could produce as much as 150 million  
kgs. of tobacco and there is enough  
market for that. Believing this, the far  
mers extended the area of tobacco cul  
tivation. But in spite of that, the rate  
has fallen, and it has led to agitation;  
auctions have been suspended and nego  
tiations started. The main demands of  
the farmers are, they want immediate  
release of the remaining 13  
million Kgs. of Russian orders and they want  
'GTC and the Tobacco Board to intervene in  
such situations. There is a Tobacco Growers  
Cooperative Union there, and they want that  
they should be given some margin money so  
that they can also in-Wvene when such  
situation arises. They also want the Tobacco  
Board to be re-aonstituted with proper  
representation to the growers on the Board,  
because the Board is oblivious to the troubles  
faced by the tobacco farmers. After a long  
agitation, ultimately, representations were  
made to the Prime Minister and also some of  
the Members of Parliament met the  
Commerce Minister. As a re-